



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 8, 1994 (पौष 18, 1915)  
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 8, 1994 (PAUSA 18, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	5	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों जिनमें (सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के द्वितीय अधिवृत्त पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	15
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	15	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निबंधक और महाबोधा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	15
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	75	भाग III—खण्ड 2—नोटिफ़ाई कार्यालय द्वारा जारी की गई नोटिफ़ाई और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिफ़ाई	19
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मूल्य आयुक्तों के प्राधिकरण के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियम, अध्यादेश और विनियमों का द्वितीय भाग में प्राविष्ट पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिफ़ाई	727
भाग II—खण्ड 2—विशेष्यक तथा विशेष्यको पर प्रवर मन्त्रियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—नैट-परकारों आदि के और और-परकारों विधियों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिफ़ाई	3
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अवेजो और द्वितीय क्षेत्रों में रक्त और रक्त के वाक्या को बनाने वाला अधिनियम	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

## CONTENTS

Page	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	5
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court. . . . .	15
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence. . . . .	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	75
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	15
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	19
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	727
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private bodies. . . . .	3
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi. . . . .	*

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संस्थों से संबंधित अधिसूचनाएं  
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 1993

संकल्प

सं० एस० सी०-1(5)/93-डी०-III (. )—दिनांक 31 जनवरी, 1986 के संकल्प सं० एस० सी०-1(1)/86-डी-III के अन्तर्गत भारत सरकार ने इस्पात और बान मंत्री की अध्यक्षता में "इस्पात उपभोक्ता परिषद्" का पुनर्संरचना किया था जिसमें सरकार, लोहे और इस्पात के उत्पादक तथा उपभोक्ता, मरान निर्माता और सम्बद्ध उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस संघटन को बाद में दिनांक 25 मई 1993 के संकल्प द्वारा कुछ और संस्थाओं/उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देकर बड़ा कर दिया गया। परिषद् का कार्यकाल जो दिनांक 31 अक्टूबर 1991 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा 30 अक्टूबर, 1993 तक बढ़ा दिया था, वह 30 अक्टूबर, 1993 को समाप्त हो गया। परिषद् के कार्यकाल को दो वर्ष अर्थात् 30 अक्टूबर, 1995 तक बढ़ा दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. मैसर्स लुधियाना इलैक्ट्रो प्लेटर्स एसोसिएशन, लुधियाना मैसर्स दुर्गापुर स्माल इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, दुर्गापुर तथा इस्पात उद्योग, खन्ना के श्री पवन सचदेवा को प्रतिनिधित्व देने के अतिरिक्त निम्नलिखित को भी प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया है :—

प्रतिनिधित्व

1. ऑल इंडिया इंडकेशन फरनेसिस एसोसिएशन  
209, एम० जी० हाउस,  
साम्बाधिक केन्द्र.

बजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र,  
दिल्ली-110052।

2. स्टील चैम्बर ऑफ इण्डिया  
418, लोहा भवन,  
पोस्ट—"जी" मेलो रोड,  
बम्बई-400009।

परिषद् के कार्य जैसे लोहा तथा इस्पात के बारे में सप्लाय, उपभोक्ता, गुणवत्ता तथा विपणन से संबंधित मामलों पर निर्णयित रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, और विभागों जिसमें प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शामिल हैं, और इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सभी सदस्यों को भेजी जाएं।

वह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सन्तोष नोटियाल  
संयुक्त सचिव

## संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 सितम्बर 1993

सं० 12-2/93-एल० आई०—पी० ओ० आई० एफ० नियमावली के नियम 28 के अनुसार डाक जीवन बीमा पालिसी को चालू रखने के लिए डाक जीवन बीमा के मासिक प्रीमियम का भुगतान महीने के पहले दिन अग्रिम में किया जाना है। इसका भुगतान ग्रेस की अवधि के दौरान भी किया जा सकता है। उस महीने के इक्कीसवें दिन तक रहता है जिस महीने का प्रीमियम देय है। यदि महीने का इक्कीसवा दिन रविवार या किसी डाक अवकाश दिवस को पड़ता है तो प्रीमियम का भुगतान अगले कार्य दिवस को किया जा सकता है।

2. उपर्युक्त नियम में संशोधन करने हुए राष्ट्रपति एतद् द्वारा यह निवेश देते हैं कि डाक जीवन बीमा पालिसी के मासिक प्रीमियम का भुगतान अब से या तो उस महीने के पहले दिन किया जा सकता है जिस महीने का प्रीमियम देय है या ग्रेस की अवधि के दौरान किया जा सकता है जो उस कैलेंडर माह के अंतिम दिन तक रहेगा जिस माह का प्रीमियम देय है, और यदि महीने का अंतिम दिन रविवार या किसी डाक अवकाश दिवस को पड़ता है तो अंतिम दिन के पहले पड़ने वाले दिन तक उसका भुगतान किया जा सकता है। तदनुसार यदि प्रीमियम का भुगतान नकद में किया जाना है तो बीमाकृत व्यक्ति अपने द्वारा चुने गए डाकघर में रकम का भुगतान उस महीने के अंतिम दिन या उससे पहले कर सकता है जिस महीने का प्रीमियम देय है और अपनी पी० आर० पुस्तिका में पोस्टमास्टर का पत्र ली ले सकता है।

3. "वेतन वसूली पालिसियों" के मामले में अब किसी विशेष महीने का प्रीमियम बीमाकृत व्यक्ति के उसी महीने के वेतन से काट लिया जाएगा किंतु मार्च के महीने को छोड़कर जब वेतन पहली अप्रैल को देय है, यह कटौती उपर्युक्त महीने के अंतिम दिन के बाद नहीं की जाए मौजूदा पालिसियों के मामले में जहां यह पाया जाए कि "अग्रिम वसूली" से बदलकर "मौजूदा वसूली" करने के परिणामस्वरूप किसी अतिरिक्त प्रीमियम का वसूला कर ली गई हो तो उसे प्रीमियम के भुगतान/वाचों के निपटान के समय वापस कर दिया जाएगा।

4. आगे इस निर्देशावली के दिनांक 26-3-87 के पक्ष सं० 26-44/86-एल० आई० के तहत शुरू की गई "ग्रुप लाइवर योजना" के अनुसार, प्रीमियमों का वसूली के संबंध में किसी संगठन/कार्यालय/संस्था के डी०डी०ओ०/कैशियर को,

जो उक्त बीमाकृत व्यक्तियों के वेतन में प्रीमियमों की वसूली करने के लिए प्राधिकृत है, जिन्होंने इस योजना का विकल्प दिया है, को यह अनुमति है कि वे किसी परिगणित बैंक में नकद में या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा देय इन प्रीमियमों से इस प्रकार जमा की गई कुल रकम एक मुक्त में उस महीने के अंतिम दिन से 7 दिनों की अवधि के भीतर जमा करें जिस महीने के ऐसे प्रीमियम देय हो गए थे और बीमाकृत व्यक्तियों के वेतन से वसूल कर लिए गए थे।

5 डाक जीवन बीमा प्रीमियमों के भुगतान में संबंधित पी० ओ० आई० एफ० नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे—

उपर्युक्त नियमों में—

5.1 नियम 1 में जीव "परिभाषा" के अंतर्गत जोड़ दिया जाए; 10 (क) "ग्रेस की अवधि" का आशय है—पालिसी चालू रखने के लिए प्रीमियम के भुगतान हेतु अनुमत ग्रेस के दिन।

10 (ख) "ग्रेस के दिन" का आशय है—पालिसी चालू रखने के लिए उक्त विशेष महीने के प्रीमियम का भुगतान करने हेतु अनुमत दिनों की वास्तविक संख्या जिस महीने के लिए यह प्रीमियम पहले दिन देय था।

14 (क) "चालू पालिसी" का आशय है—वह पालिसी जिसके सभी देय प्रीमियमों का नियमित रूप से भुगतान कर दिया गया हो और ऐसी पालिसी पी० ओ० आई० एफ० के किसी नियम के तहत न रद्द हुई हो और न व्यपन्न हुई हो।

मौजूदा उपनियम "14" को उपनियम 14 ख के बतौर पुनर्जकित किया जाए।

5.2 नियम 2 (क) के नीचे टिप्पणी 2—लाइन 6 में प्रतिस्थापित करें

"21 तारीख" को "महीने के अंतिम दिन (मार्च के मामले में 1 अप्रैल)" से

5.2.1 लाइन 7 में प्रतिस्थापित करें

"21 तारीख" को "महीने के अंतिम दिन (मार्च के मामले में 1 अप्रैल)" से

5.3 नियम 28 लाइन 7—प्रतिस्थापित करें

"पूर्ववर्ती महीने के" को "उपर्युक्त महीने के" से।

5.3.1	(i) लाईन 8-9 प्रति- स्थापित करें	5.3.3 नियम 28 का फुटनोट छोड़ दें।
	“मई महीने के वेतन” को “जून महीने के वेतन” से तथा “मई महीने के अंतिम कार्य दिवस” को “जून महीने के अंतिम कार्य दिवस (मार्च के महीने को छोड़कर जिसका वेतन अप्रैल महीने के पहले कार्य दिवस को प्राप्त होता है)” से।	5.3.4 नियम 28 के नीचे टिप्पणी-1 लाईन - 8 प्रतिस्थापित करें “21 तारीख” को “अंतिम दिन (मार्च के मामले में 1 अप्रैल)” से लाईन-9 में—प्रतिस्थापित करें “पूर्ववर्ती महीने का” को “उपर्युक्त महीने का” से
5.3.2	(ii) लाईन 9 में प्रति - स्थापित करें	5.3.5 नियम 28 के नीचे टिप्पणी-1 का फुटनोट छोड़ दें।
	“यदि प्रीमियम की अदायगी नकद रूप में की जानी हो तो बीमाकृत व्यक्ति को उसके द्वारा चुने गए डाकघर में उस महीने की 21 तारीख को या उससे पहले इसकी अदायगी करनी चाहिए जिस महीने के लिए प्रीमियम देय है तथा अपनी प्रीमियम रसीद वही में पोस्टमास्टर से इसकी रसीद प्राप्त करनी चाहिए “को” यदि प्रीमियम की अदायगी नकद रूप से की जानी हो तो बीमाकृत व्यक्ति को उसके द्वारा चुने गए डाकघर में उस महीने की 1 तारीख का जिस महीने के लिए प्रीमियम देय है या ऐसे की अवधि के भीतर इसकी अदायगी करनी चाहिए जिसकी अवधि एक कैलेंडर महीना से अधिक नहीं होगी और इसे उस महीने की 1 तारीख से गिना जाएगा जिस महीने के लिए प्रीमियम देय है तथा अपनी प्रीमियम रसीद वही में पोस्टमास्टर से इसकी रसीद प्राप्त करनी चाहिए” से।	5.3.6 नियम 28 के नीचे टिप्पणी-4 पहली लाईन में प्रतिस्था- पित करें “21 तारीख” को “महीने के अंतिम दिन (मार्च के मामले में 1 अप्रैल)” से 5.3.7 नियम 28 के नीचे टिप्पणी-5 लाईन-6 में प्रतिस्थापित करें “21 तारीख” को “महीने के अंतिम दिन (मार्च के मामले में 1 अप्रैल)” से 5.3.8 नियम 28 के नीचे टिप्पणी-5 का फुटनोट छोड़ दें।
		5.4 नियम 31 (2) लाईन-4 में प्रतिस्थापित करें “21 तारीख” को “महीने के अंतिम दिन (मार्च के मामले में 1 अप्रैल)” से
		5.5 नियम 36 लाईन-3 में प्रतिस्थापित करें “21 तारीख” को “महीने के अंतिम दिन (मार्च के मामले में 1 अप्रैल)” से
		5.5.1 नियम 36 का फुटनोट छोड़ दें

5.5.2 नियम 36 के नीचे टिप्पणी	लाइन 10 में प्रतिस्थापित करें “21 तारीख” को “महीने के अंतिम दिन (मार्च के मामले में—1 अप्रैल)” में
5.5.2 नियम 36 के नीचे टिप्पणी का फुटनोट	छोड़ दें।
5.6 नियम 39 (1)	“21 तारीख” को “महीने के अंतिम दिन (मार्च के मामले में—1 अप्रैल)” में
5.7 नियम 40 (1)	लाइन 2 में प्रतिस्थापित करें “21 तारीख” को “महीने के अंतिम दिन (मार्च के मामले में—1 अप्रैल)” में।
5.7.1 नियम 40 (1)	लाइन 2 में प्रतिस्थापित करें “21 तारीख” को “महीने के अंतिम दिन (मार्च के मामले में—1 अप्रैल)” में।
5.8 परिशिष्ट के अंतर्गत उन नियम 12 के नीचे फॉर्म-II का टिप्पणी 3	लाइन 5 में प्रतिस्थापित करें “21 तारीख” को “महीने के अंतिम दिन (मार्च के मामले में—1 अप्रैल)” में

उपर्युक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे

डी० के० बुद्धी,  
निदेशक (पी०एल०आई०)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 दिसम्बर 1993

सं० 23-1/92-एल०आई०--भारत के राष्ट्रपति डाकघर बीमा निधि नियमों में निम्नलिखित संशोधन तत्काल लागू करने का सहर्ष निर्देश देते हैं, अर्थात्

1. मौजूदा नियम 39 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा—

39 (1) जहां पालिसी स्वीकार करने की तारीख से 36 माह के भीतर मृत्यु हो जाती है उन पालिसियों के संबंध में दावों का निपटारा।

किसी पालिसी के संबंध में यदि पालिसी स्वीकार करने की तारीख से 36 माह ममाप्त होने से पहले मृत्यु हो जाती है और देय प्रीमियम/प्रीमिया उस महीने की पहली तारीख को, जिसके लिए वह देय है, या नियम 28 के अनुसार अनुमत्य छूट की अवधि के भीतर अदा नहीं किया जाता है तो पालिसी रद्द हो जाएगी और इसलिए लाभ संबंधी सभी दावे समाप्त हो जाएंगे और उसके फलस्वरूप अदा की गई सभी राशियां इसके पश्चात् निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर जप्त कर ली जाएंगी,

(i) वशत कि, इस नियम के प्रयोजन के लिए, किसी महीने के प्रीमियम को तब तक बकाया नहीं समझा जाएगा जब तक कि बीमाकृत व्यक्ति उससे ठीक पहले महीने के वेतन, पेंशन या निर्वाहन के दौरान निर्वाह भत्ते या भारत में छुट्टी पर होने पर किसी छुट्टी भत्ते को देय होने पर अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण न ले सका हो। नियम 28 की टिप्पणी 4 और नियम 36 के नीचे दी गई टिप्पणी भी देखें।

(ii) यह भी शर्त है कि उपर्युक्त उपबंध (i) उन बीमादारों के संबंध में लागू नहीं होगा जो अपना प्रीमियम/प्रीमिया तत्कद अदा करते हैं।

(2) उपर्युक्त का विचार किए बिना यदि पालिसी स्वीकार करने की तारीख से 36 माह के भीतर बीमाकृत व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है तो जिन पालिसियों का प्रीमिया नियम 28 के अंतर्गत अनुमत्य छूट की अवधि के भीतर अदा नहीं होता है उनके पक्ष में शर्तित अवधि की छूट निम्न प्रकार दी जाएगी:—

(i) यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पालिसी स्वीकार करने की तारीख से छः माह के भीतर हो जाती है तो छूट की अवधि के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(ii) यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पालिसी स्वीकार करने की तारीख से छः माह के बाद किंतु 12 माह के भीतर होती है तो छूट की अवधि के अलावा 30 दिन की छूट और दी जाएगी।

(iii) यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पालिसी स्वीकार करने की तारीख से 12 माह के बाद किंतु 24 माह के भीतर होती है तो छूट की अवधि के अलावा 60 दिन की छूट और दी जाएगी।

(iv) यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पालिसी स्वीकार करने की तारीख से 24 माह के बाद किंतु 36 माह के भीतर होती है तो छूट की अवधि के अलावा 90 दिन की छूट और दी जाएगी।

(v) यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु उपर्युक्त उपनियम 2 (i), (ii), (iii) और (iv) के अनुसार अनुमत्य छूट की अवधि के दौरान और बकाया देय प्रीमियम/प्रीमिया की ब्याज सहित अदायगी से पहले होती है

तो पालिसी फिर भी वैध मानी जाएगी और बीमाकृत व्यक्ति के नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी को, जैसा भी मामला हो, बाँचे की रकम में से अदेय प्रीमियम/प्रीमिया को, उस पर लगे ब्याज की दर सहित जो डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित की जाएगी, घटाने के पश्चात् शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(3) यदि रद्द पालिसी को रखने वाला कोई पालिसी-धारक उस पालिसी का प्रथम बकाया प्रीमियम देय होने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर अपनी पालिसी बहाल कराना चाहे तो वह अदायगी की तारीख तक सभी बकाया प्रीमियम/प्रीमिया डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित की गई दर में ब्याज सहित उस पालिसी के संबंध में प्रीमिया की अदायगी के लिए निर्निर्दिष्ट डाकघर में जमा कर सकता है और इस संबंध में पी०पी०एम०जी० को निर्धारित प्रपत्र में बीमादार द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किया हुआ निरंतर अच्छा स्वास्थ्य रहने का प्रमाण पत्र और अपने नियोजन का इस बात का प्रमाण पत्र कि कथित बीमादार ने उक्त पालिसी का प्रथम बकाया प्रीमियम देय होने की तारीख से बकाया अदायगी की तारीख तक की अवधि में बीमारी के आधार पर कोई छुट्टी नहीं ली थी और कथित डाकघर से प्राप्त रसीद (ए०सी०जी०-67) की प्रति भेजकर सूचित कर सकता है। पालिसी की बहाली बीमादार या विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की अनिश्चित कार्रवाई के बिना सम्पन्न होगी बशर्ते कि बकाया अदायगी के समय जीवन बीमा को प्रोत्पन्न बनी रहे।

(i) बशर्ते कि यदि प्रीमियम के भुगतान के आशय से किया गया कोई भुगतान उपर्युक्त छः माह की अवधि के दौरान किया जाए और यदि उसमें ब्याज सहित वह संपूर्ण बकाया शामिल न हो जो इस बात के लिए अपेक्षित हो कि पालिसी रद्द न हो, तो ऐसे भुगतान को मिलम्बित माना जाएगा और उसे जीवन बीमा जोखिम के प्रीमियमों के रूप में किया गया भुगतान नहीं माना जाएगा। यदि प्रीमियम/प्रीमिया के निलम्बन के दौरान बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और पालिसी बहाल नहीं होती है तो विभाग पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं होगा। निलम्बन में रखे गए ऐसे प्रीमियम को पालिसीधारक या उसके नामिती या उसके कानूनी उत्तराधिकारी जैसा भी मामला हो, के आवेदन करने पर डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा।

टिप्पणी : नियम 39 (3) और नियम 40 (4) के अधीन पालिसी की बहाली को अनुमति पालिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिक से अधिक दो बार दी जाएगी।

टिप्पणी 2 : तथापि, डाक महानिदेशक को यह विवेकाधिकार है कि विशेष मामलों में वह किसी पालिसी या

उसके किसी भाग की, ब्याज सहित या बिना ब्याज के, अनुग्रहपूर्वक अदायगी कर सकता है, बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि नियमों का उल्लंघन, जानबूझकर इस उद्देश्य के साथ नहीं किया है कि जिसमें इसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और परिस्थितियाँ पालिसी राशि के भुगतान को उचित ठहराये।

2. मौजूदा नियम 40 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

जो पालिसियाँ, पालिसी स्वीकार करने की तारीख से 36 माह के बाद समाप्ती रही हैं उनके संबंध में दावों का निपटारा।

40 (i) किसी पालिसी के संबंध में यदि वह पालिसी स्वीकार करने की तारीख से 36 माह तक प्रभावी रही है और इस अवधि के बाद देय प्रीमियम/प्रीमिया उस महीने की पहली तारीख को जिसके लिए वह देय है या नियम 23 के अनुसार अनुमत्य छुट्टी के अवधि के भीतर अदा नहीं किया जाता है तो वह पालिसी प्रथम बकाया प्रीमियम देय होने की तारीख से 12 महीने समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेगी,

(i) बशर्ते कि, इस नियम के प्रयोजन के लिए, किसी महीने के प्रीमियम को तब तक बकाया नहीं समझा जाएगा जब तक कि बीमाकृत व्यक्ति उससे ठीक पहले वाले महीने के वेतन, पेंशन या निलम्बन के दौरान निर्वाह भत्ते या भारत में छुट्टी होने पर किसी छुट्टी भत्ते को देय होने पर अपने नियंत्रण से बाहर को परिस्थितियों के कारण न ले सका हो। नियम 28 की टिप्पणी 4 और नियम 36 के नीचे दी गई टिप्पणी भी देखें।

(ii) यह भी शर्त है कि उपर्युक्त उपबंध (i) उन बीमादारों के संबंध में लागू नहीं होगा जो अपना प्रीमियम नकद अदा करने हैं।

(2) प्रथम बकाया प्रीमियम देय होने की तारीख से 12 महीने को कथित अवधि के भीतर बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने या सावधि बीमा की अवधि समाप्त होने के कारण यदि पालिसी के संबंध में दावा बनता है तो पालिसी की अदायगी के लिए किया जाने वाला दावा प्रीमियम/प्रीमिया की समस्त बकाया राशि और उस पालिसी के संबंध में प्रथम बकाया प्रीमियम देय होने की तारीख से पालिसी के दावा बनने की तारीख तक डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज तथा संचित कर्ज की राशि यदि कोई हो और उस पर ब्याज की कटौती करके स्वीकार किया जाएगा।

(3) यदि 12 महीने की कथित अवधि के भीतर बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने या सावधि बीमा की अवधि समाप्त होने पर पालिसी के संबंध में दावा नहीं बनता और अभ्यर्पण मूल्य या प्रदत्त पालिसी के संबंध में उस अवधि के भीतर कोई आवेदन

प्राप्त नहीं होता तो पालिसी केवल अपने प्रदत्त मूल्य के लिए स्वतः सक्रिय बनी रहेगी, बशर्ते कि वह प्रदत्त मूल्य 100 रुपए से कम नहीं हो।

- (i) यह भी शर्त है कि यदि प्रदत्त मूल्य 100 रुपए से कम हो तो आवेदन करने पर केवल अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा और उसपर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) यदि उपर्युक्त उप नियम (1) की शर्तों के अनुसार अप्रभावी पालिसी को रखने वाला पालिसी धारक उस पालिसी का प्रथम बकाया प्रीमियम देय होने की तारीख से 12 माह की अवधि के भीतर अपनी पालिसी बहाल कराना चाहे तो वह अदायगी की तारीख तक सभी बकाया प्रीमियम/प्रीमिया और उसका निर्धारित दर पर ब्याज उस पालिसी के संबंध में प्रीमिया की अदायगी के लिए निर्निर्दिष्ट डाकघर में जमा कर सकता है तथा इस संबंध में सी०पी०एम०जी० को निर्धारित प्रपत्र में बीमादार द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किया हुआ निरंतर अच्छा स्वास्थ्य रहने का प्रमाण पत्र और अपने नियोक्ता का इस बात का प्रमाण पत्र कि कथित बीमादार ने उक्त पालिसी का प्रथम बकाया प्रीमियम देय होने की तारीख से अदायगी की तारीख तक की अवधि में बीमारी के आधार पर कोई छुट्टी नहीं ली थी और कथित डाकघर से प्राप्त रसीद (ए०सी०जी०-67) की प्रति भेजकर सूचित कर सकता है। पालिसी की बहाली बीमादार या विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त कार्रवाई के बिना स्वचालित होगी बशर्ते कि बकाया अदायगी के समय जीवन बीमा की योग्यता बनी रहे।

- (i) बशर्ते कि यदि प्रीमियम के भुगतान के आशय से कोई भुगतान ऊपर उप नियम (4) में निर्दिष्ट 12 महीने की कथित अवधि के दौरान किया जाए और यदि उसमें ब्याज सहित वह संपूर्ण बकाया शामिल न हो जो इस बात के लिए अपेक्षित हो कि पालिसी 12 माह तक प्रभावी बनी रहे तो ऐसे भुगतान को निर्रखित माना जाएगा और उसे जीवन बीमा जोखिम के प्रीमियमों के रूप के किया गया भुगतान नहीं माना जाएगा। यदि प्रीमियम के निर्रखन के दौरान बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और पालिसी बहाल नहीं होती है तो विभाग पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं होगा। निर्रखन में रखे गए ऐसे प्रीमियम को पालिसी धारक या उसके नामिती या उसे कानूनी उत्तराधिकारी जैसा भी मामला हो, को आवेदन करने पर डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा।

- (ii) ऐसी पालिसियों के संबंध में जिनके लिए वार्षिक प्रीमियम पहले से ही नकद अदा किया गया है कोई प्रीमियम लौटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाए मृत्यु के कारण किए गए दावों के मामले में असमाप्त महीनों के लिए प्रीमियम लौटा दिया जाएगा।

टिप्पणी: नियम 39(3) और नियम 40(4) के अधीन पालिसी की बहाली की अनुमति पालिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिक से अधिक दो बार दी जाएगी।

- (3) मौजूदा नियम 41 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा,

पालिसियों का पुनः प्रवर्तन

41(1) डाक महानिदेशक या उनकी ओर से मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, ऐसी किसी पालिसी के संबंध में जो नियम 40(1) के अधीन रद्द हो गई है अथवा नियम 40(1) के अधीन सक्रिय न रही हो और नियम 39(3) या नियम 40(4) के उपबंधों के अधीन बहाल नहीं की गई हो, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर अपने विवेकानुसार उसे पुनः प्रवर्तन की अनुमति इस शर्त पर दे सकता है कि कथित पालिसी परिपक्व नहीं हुई है और बीमाकृत व्यक्ति पुनः प्रवर्तन के समय बीमायोग्य है। ऐसे पुनः प्रवर्तन डाक महानिदेशक या चीफ पोस्टमास्टर जनरल द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख के भीतर, डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख के भीतर, डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित दरों पर प्रीमियम की सभी बकाया राशियों के उस पर लगे ब्याज सहित, भुगतान की पात्र होगी और उसका परिकलन ऐसी पालिसी के प्रथम बकाया प्रीमियम के देय होने की तारीख से किया जाएगा बशर्ते कि नियोक्ता इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि पालिसी धारक ने पिछले एक वर्ष के दौरान या संपूर्ण सेवावधि के दौरान इनमें से जो भी सबसे कम हो, चिकित्सा आधार पर कोई छुट्टी नहीं ली थी और किसी प्राधिकृत चिकित्सा एजेंट का निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए कि बीमाकृत व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य और आदतों को देखते हुए बीमे के योग्य है, और उसके अपने या परिवारकृत या व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

- (2) कोई भी पालिसी उसी समय तक पुनः प्रवर्तित की गई मानी जाएगी जब तक कि इस प्रयोजन के लिए कोई आवेदन न दिया गया हो तथा जब तक कि पालिसी औपचारिक रूप से लिखित रूप में पुनः प्रवर्तित न कर दी गई हो।

- (3) प्रीमियम/प्रीमिया के भुगतान के आशय से किया गया कोई भुगतान यदि नियम 39(1) के अधीन पालिसी रद्द होने अथवा नियम 40(1) के अधीन सक्रिय न रहने के बाद किया जाए किंतु उपर्युक्त उप नियम (1) और (2) के अधीन पालिसी के



औपचारिक रूप से पुनः प्रवर्तित किए जाने से पहले किया जाए तो ऐसे भुगतान को निलंबित माना जाएगा और उसे जीवन बीमा जोखिम के प्रीमियम/प्रीमिया के रूप में किए गए भुगतान के रूप में नहीं माना जाएगा। यदि प्रीमियम/प्रीमिया के निलंबन के दौरान बीमाकृत व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है और पालिसी पुनः प्रवर्तित नहीं होती है तो विभाग पर किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं होगा। निलंबन में रखे गए ऐसे प्रीमियम को पालिसीधारक या उसके तामिली या उसके कानूनी उत्तराधिकारी जैसा भी मामला हो, को आवेदन करने पर डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा।

- (4) डाक महानिदेशक या उनकी ओर से मुख्य पोस्ट-मास्टर जनरल ऐसी पालिसी को पुनः प्रवर्तित करने के संबंध में जो नियम 39(1) के अधीन रद्द हो गई हो या नियम 40(1) के अधीन अक्रिय न रही हो, पात्र मामलों में लिखित रूप में आवेदन जारी होने पर अपने विवेकानुसार बकाया प्रीमियम तथा उस पर देय ब्याज की अदायगी अधिक से अधिक बारह आसान किस्तों में करने की अनुमति दे सकता है। ऐसे मामलों में जीवन बीमा जोखिम पहली किस्त जमा करने की तारीख से शामिल किया जाएगा बशर्ते कि उसके बाद उत्तरवर्ती किस्तें और सामान्य मासिक प्रीमिया तथा बकाया राशि जब भी देय हो उन्हें नियमित रूप से जमा किया गया हो। जो बीमादार डाक महानिदेशक या सी०पी०एम०जी० के निर्देशानुसार बकाया राशि की किस्तें और सामान्य मासिक प्रीमिया जब भी देय हों, नियमित रूप से जमा कर रहा है उसकी मृत्यु होने पर इस बात का विचार किए बिना कि मृत्यु के समय तक प्रीमिया की कुछ बकाया राशि जमा नहीं हुई थी, कथित पालिसी का दावा प्रीमिया के ऐसे बकाया और उस पर ब्याज तथा कर्ज की राशि यदि कोई हो और उस पर ब्याज दावे की रकम से काटकर स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी: नियम 41 के अधीन पालिसी के पुनः प्रवर्तन की अनुमति पालिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिक से अधिक दो बार दी जाएगी किंतु इसमें पुनः बहाली के लिए नियम 39(3) और 40(4) के अधीन दी गई छूट शामिल नहीं होगी।

- (4) उपर्युक्त संशोधन से प्रभावी होंगे। किंतु डाक जीवन बीमा के जिन बीमाधारों ने अपनी पालिसी कथित तारीख से पहले ली है वे डाकघर बीमा विधिविधिम (दिनांक 30-9-85 तक संशोधित) के आरंभ में परिभाषा से पहले विधि टिप्पणी के अनुसार नौ बूझा नियमों द्वारा शासित होने के लिए विकल्प दे सकते

हैं किंतु उन्हें इस भाग का लिखित रूप में विकल्प दावा प्रस्तुत करते समय अवकाश से पहले देना होगा।

डी० के० बुक्की,  
निदेशक (पी०एल०आई०)

#### संचार मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 नवम्बर 1993

सं० 23-2/84-एल० आई०--राष्ट्रपति एतद्वारा यह निर्देश देते हैं कि "गैर चिकित्सा योजना" के अंतर्गत होने वाले बीमे को राशि की अधिकतम सीमा तत्काल 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये) से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) कर दी जाए।

पी०ओ० आई०एफ० नियमों के नियम 14 में विम्वलिखित संशोधन तत्काल लागू होंगे, अर्थात् :

कथित नियमों में ;

मौजूबा नियम 14, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए  
14 (1). चिकित्सा योजना

ऐसे प्रत्येक मामले में जहां जीवन बीमा, बंधोबस्ती बीमा या प्रत्याशित बंधोबस्ती बीमा का प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाता है वहां प्रस्तावक को अनिवार्यतः निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराना होगा और प्रस्तावक का ऐसा बीमे के लिए उक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा योग्य घोषित होना अनिवार्य होगा।

(क) बशर्ते कि यदि प्रस्तावक चिकित्सा परीक्षण कराने के उपरांत, पालिसी करवाने का अपना विचार बदल लेता है या यह तय कर लेता है कि उसे पालिसी के प्रस्ताव से संबंधित आगे की प्रक्रिया का पालन नहीं करना है, या वह नियत तारीख को अपना पहला प्रीमियम अदा नहीं कर पाता या एक बीमाकृत व्यक्ति पालिसी छोड़ देता है और पालिसी लागू होने के 12 माह पूरे होने से पूर्व ही प्रीमिया का भुगतान करना बन्द कर देता है तो उरो चिकित्सा परीक्षण के लिए नियम 19 और 21 में निर्धारित शुल्क अदा करना होगा, जो या तो नकद प्रयुक्त किया जाएगा या उसको देय अगले वेतन में के, तैसो मो स्थिति हो, काट लिया जाएगा।

(ब) चिकित्सा परीक्षण निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा नियम 19 के अनुसार किया जाएगा जो बीमाराशि पर निर्भर करेगा तथा चिकित्सा परीक्षण शुल्क नियम 21 के अनुसार विभाग द्वारा बूझा किया जाएगा। तथापि, यदि द्वितीय चिकित्सा मत मत करने को आवश्यकता पड़ता है और यदि प्रस्तावक प्रीमिया का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं कर पाता और वह प्रीमिया के विलम्ब से भुगतान के लिए उत्तरदायी है

तो निम्न 22 के तहत विनियम 1 के अनुसार चिकित्सा परीक्षण शुल्क का भुगतान प्रस्तावक द्वारा किया जाएगा।

## (2) गैर चिकित्सा योजना

(i) कोई भी व्यक्ति, भले ही वह पुरुष हो या महिला जिसकी आयु उसके अगले जन्मदिवस को 35 वर्ष से अधिक न हो और जो पी०ओ०आई०एफ० नियमों के नियम 2, 2ए, 2बी या 2 सी के अंतर्गत डाक जीवन बीमा पालिसी के लिए पात्र है इनमें विनियमित व्यक्ति, डाक-तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय एजेंट, भूतपूर्व कर्मचारी तथा ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिनसे गैर-चिकित्सा या चिकित्सा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा पालिसी के लिए आवेदन किया है और जिसका आवेदन भारत में कार्य कर रही किसी भी बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, निर्धारित प्रपत्र में गैर-चिकित्सा योजना के लिए बीमाकृत धनराशि के लिए 10,000 (दस हजार रुपये) रुपये के गुणकों में आवेदन कर सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा अन्य किसी गैर-चिकित्सा पालिसी/पालिसियों, जिनका प्रस्तावक धारक है या उक्त गैर-चिकित्सा योजना के अंतर्गत धारक होने का प्रस्ताव रखता है, सहित 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) होगी, अन्य किसी गैर-चिकित्सा या चिकित्सा पालिसी/पालिसियों सहित, जिनका प्रस्तावक धारक है या धारक होने वाला है, इस राशि की अधिकतम सीमा 2,00,000 (दो लाख रुपये) होगी।

(क) बशर्ते कि प्रस्तावक का चिकित्सा-इतिहास किसी प्रतिकूल लक्षण को प्रकट न करे और यदि ऐसा होगा तो प्रस्तावक पी०ओ०आई०एफ० नियमों के नियम 2, 2 ए, 2 बी तथा 2 सी के अंतर्गत किसी भी वर्ग में सूचिबद्ध हो जाएगा, जो कि प्रस्ताव के समय चिकित्सा वर्ष ए-1 में है और जिसे प्रस्ताव की तारीख से पूर्व दो वर्षों के दौरान निम्न चिकित्सा वर्ग में पदावत नहीं किया गया था।

(ii) इस योजना के अंतर्गत केवल 40.50, 55.58 तथा 60 वर्ष की आयु में परिपक्व होने वाली धुंदीबस्ती बीमा पालिसी जारी की जाएगी।

(iii) इस नियम के अंतर्गत जारी गैर-चिकित्सा पालिसी के मामले में यदि पालिसी परिपक्वता से पूर्व ही दावे के योग्य हो जाती है तो कथित पालिसी के अनुसार कुल बीमित राशि के बावजूब ऐसे दावों पर भुगतान निम्नलिखित धनराशि तक सीमित रहेगा;

(क) यदि बीमादार की मृत्यु प्रस्ताव की स्वीकृति के एक वर्ष के पूर्ण होने से पूर्व हो जाती है तो प्रोद्भूत बोनस के साथ बीमाकृत राशि का 35 प्रतिशत।

(ख) यदि बीमादार की मृत्यु, प्रस्ताव की स्वीकृति के 2 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व, किन्तु 1 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व नहीं, हो जाती है तो प्रोद्भूत बोनस के साथ बीमाकृत राशि का 60 प्रतिशत।

(ग) यदि बीमादार व्यक्ति की मृत्यु, प्रस्ताव स्वीकृत होने की तारीख से तीन वर्ष पूर्ण होने से पूर्व, किन्तु दो वर्ष पूर्ण होने से पूर्व नहीं, हो जाती है तो प्रोद्भूत बोनस सहित बीमाकृत राशि का 60 प्रतिशत।

(घ) यदि बीमादार व्यक्ति की मृत्यु प्रस्ताव की स्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत होती है तो प्रोद्भूत बोनस सहित पूरी बीमाकृत राशि।

2. इसे डाक वित्त की सहमति से उनकी जायरी संख्या 2956-एफ०ए०/93, दिनांक 1-11-93 द्वारा जारी किया गया।

डी० के० बुद्धी,  
निदेशक (डाक जीवन बीमा)

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 31st December 1993

## RESOLUTION

No. SC-1(5)/93-D.III.—Vide Resolution No. SC-1(1)/86-D.III dated 31st January, 1986, Government of India had constituted a Steel Consumers Council under the Chairmanship of the Minister of Steel & Mines and consisting of representatives of Government, producers and consumers of iron and steel, house builders and related industries. Its composition was enlarged subsequently vide Resolution dated 25th May, 1993 by giving representation on it to some more Associations/Industrialists. The tenure of the Council which was extended upto 30th October, 1993 vide Resolution of even number dated 31st October 1991 expired on 30th October, 1993. It has now been decided to extend the tenure of the Council by another two years i.e. upto 30th October, 1995.

2. In addition to the representation given to M/s. Ludhiana Electroplaters Association, Ludhiana, M/s. Durgapur Small Industries Association, Durgapur and Shri Pawan Sachdeva of Ispat Udyog, Khanna it has been further decided to give representation to the following on this council:

## Representation :

1. All-India Induction Furnaces Association, 209, M. G. House, Community Centre, Wazir Pur Industrial Area, Delhi-110 052.
2. Steel Chamber of India, 418, Loha Bhavan, P. D'Mello Road, Bombay-400 009.

The functions of the Council i.e. "to advise and assist Central Government on matters relating to supply, availability, quality and the market trends of the iron and steel", will remain unchanged.

## ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers Council.

Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

S. NAUTYAL, Jt. Secy.

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

## (DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 24th September 1993

No. 12-2/93-LI.—As per rule 28, of POIF Rules the monthly PLI premium is to be paid on the first day of the month in advance to keep a PLI policy in force. It can also be paid during the period of grace which is up to the 21st day of the month for which the premium is due, or the next business day, if the 21st day falls on Sunday or a postal holiday.

2. In modification of the aforesaid rule, the President hereby directs that the monthly premium of a PLI policy may now be paid either on the first day of the month for which the premium is due, or during the period of grace which shall extend up to the last day of the calendar month for which the premium is due, or the day before the last day if the last day of the month falls on a Sunday or a Postal holiday. Accordingly, if premium is to be paid in cash, the insured person must pay the amount at the Post Office selected by him on or before the last day of the month for which the premium is due and obtain Postmaster's receipt in his P. R. Book.

3. In respect of 'Pay recovery policies', the premium for a particular month shall now be deducted from the Insurant's Salary of the same month but not later than the last day of the said month except in the case of the month of March where the salary is payable on 1st April. In the case of existing policies, where it is found that an extra premium has been received as a result of switchover from the 'advance

recovery' to 'current recovery', such premium shall be refunded at the time of maturity/settlement of claims.

4. Further, in respect of recovery of premium under 'Group leader Scheme' introduced vide this Directorate letter No. 26-44/86-LI, dated 26-3-1987, the DDO/Cashier of an organisation/office/institution authorised to recover the premium from the salary of the insured persons who have opted for such scheme are allowed to deposit in lump sum the total amount thus collected on account of such premium, either in cash or through Demand Draft, drawn on any scheduled Bank, within a period of 7 days from the last day of the month for which such premium had become due and had been recovered from the salary of the insured persons.

5. The following amendments shall be made in the POIF Rules relating to payments or PLI Premium, namely:—

In the said rules—

5.1 Under the Head 'Definitions', in Rule 1, insert:  
10(a). 'Period of Grace' means the days of grace allowed for payment of premium to keep the policy in force.

10(b). 'Days of Grace' means the actual number of days allowed to pay the premium of a policy for a particular month for which it is due beyond the first of the said month to keep the policy in force.

14(a). 'Policy in force' means a policy for which all the due premium have been paid regularly and such policy has neither become 'Void' nor 'Lapsed' under any rule of POIF Rules.

## Renumber the existing sub Rule '14' as sub-Rule 14 (b)

- |        |                                   |  |
|--------|-----------------------------------|--|
| 5.2    | Note 2 below Rule 2(A)            | In line 6 substitute—"21st day" by "the last day of the month (In case of March—1st April)."   |
| 5.2.1  |                                   | In line 7 substitute "21st day" by "the last day of the month (In case of March—1st April)."   |
| 5.3    | Rule 28                           | Line 8 substitute—"For the preceding month" by "for the said month."   |
| 5.3.1  |                                   | (i) Line 10 substitute—"Pay for May" by "Pay for June" and "last working day of May" by "last working day of June (except for the month of March, pay for which is drawn on the 1st working day of April)".  |
| 5.3.2. |                                   | (ii) Line 10 substitute—"If the premium is to be paid in cash insured person must pay the amount at the Post-Office selected by him on or before, the 21st of the month for which the premium is due and obtain the Postmaster's receipt for it in his premium receipt book" by<br><br>"If the premium is to be paid in cash, the insured person must pay the amount at the Post Office selected by him either on the first day of the month for which premium is due or within the period of grace which shall not exceed one calendar month reckoned from the first day of the month for which the premium is due and obtain the Postmaster's receipt for it in his premium receipt book." |
| 5.3.3. | Foot Note of Rule 28              | Omit   |
| 5.3.4. | Note 1 below Rule 28              | In line 10 substitute—"21st" by "the last day (In case of March—1st April)".<br><br>In line 11 substitute—"For the previous month" by "for the said month".  |
| 5.3.5. | Foot Note to Note 1 below Rule 28 | Omit   |

5.3.6.	Note 4 below Rule 28	<i>In the first line. substitute—"21s by t""the last day of the month (in case of March—1st April)"</i>
5.3.7.	Note 5 below Rule 28.	<i>In line 6 substitute—"21st" by "the last day of the month (In case of March—1st April)".</i>
5.3.8.	Foot Note to Note 5 below Rule 28	Omit.
5.4.	Rule 31(2)	<i>In line 6 substitute —"21st day" by "the last day of the month "(In case of March—1st April)."</i>
5.5.	Rule 36	<i>In line 3 substitute—"21st day" by "the last day of the month" (In case of March—1st April)</i>
5.5.1.	Foot Note to Rule 36	Omit.
5.5.2.	Foot Note to Rule 36	<i>In line 14 substitute —"21st day" by "the last day of the month (In case of March—1st April)".</i>
5.5.3.	Foot Note to Note below Rule 36	Omit.
5.6.	Rule 39 (1)	<i>In line 2 substitute—"21st day" by "the last day of the month (In case of March—1st April)".</i>
5.7.	Rule 40 (1)	<i>In line 2 substitute—"21st day" by "the last day of the month (In case of March—1st April)".</i>
5.7.1.	Rule 40(1)	<i>In line 3 substitute—"21st day" by "the last day of the month (In case of March—1st April)".</i>
5.8.	Note 3 of Form II below Sub-rule 12 under Appendix	<i>Substitute in last line—"21st day" by "the last day of that month (In case of March—1st April)."</i>

The aforesaid amendments shall be effective from the date of issue of this notification.

D. K. BUDKI  
Director (PLI)

The 1st December 1993

No. 23-1/92-LI.—The President of India, is pleased to direct that, with immediate effect, the following amendments shall be made in the Post Office Insurance Fund Rules, namely :—

1. Existing Rule 39, shall be substituted by the following—

39(1) Settlement of claims in respect of policies where death takes place within thirty-six months from the date of acceptance of policy.

If, in the case of a policy where death takes place before the completion of thirty-six months from the date of acceptance of the policy and where any premium/premia have become due, be not paid either on first day of the month for which the premium is due or within the period of grace allowed as per Rule 28, the policy shall become void, and all claims to any benefit in virtue thereof shall cease and all monies that have been paid in consequence thereof shall be forfeited except in cases mentioned hereafter;

- (i) Provided that, for the purpose of this rule, an insured person is not to be considered as in arrears of premium for any month so long as he has not been able to draw his pay, pension, or subsistence allowance during suspension, or if the insured person is on leave in India, any leave allowance though due, for the month next before it due to circumstances beyond his control. See also Note-4 to Rule 28 and Note below Rule 36

- (ii) Provided further that the proviso (i) above shall not be applicable to the insureds who pay their premium/premia in cash.

(2) Notwithstanding what is stated above, if death of the life assured occurs within thirty-six months from the date of acceptance of the policy, a further period of remission shall be allowed in respect of such policies where premia remain unpaid beyond the period of grace permitted under Rule 28 in the following manner;

- (i) If the death of the life assured occurs within six months of the date of acceptance of the policy, no remission period beyond the days of grace shall be allowed.
- (ii) If the death of the life assured occurs within twelve months but not before completion of six months from the date of acceptance of the policy, a remission period of thirty days shall be allowed in addition to the period of grace.
- (iii) If the death of the life assured occurs within twenty-four months but not before the completion of twelve months from the date of acceptance of the policy, a remission period of sixty days shall be allowed in addition to the period of grace.
- (iv) If the death of the life assured occurs within thirty-six months but not before completion of twenty-four months from the date of acceptance of the policy, a remission period of ninety days shall be allowed in addition to the period of grace

(v) In the event of death of the life assured taking place during the period of remission allowed as per sub-rule (39)(2)(i)(ii)(iii) and (iv) above and before payment of arrears of premium/premia that had become due alongwith interest thereon, the policy shall still be considered valid and the sum assured paid to the nominee or legal heir of the insured as the case may be after the deduction of unpaid premium/premia from the claim amount alongwith interest thereon at such rate as may be prescribed by Director General of Posts.

(3) In the event of a policy-holder of a void policy desiring re-instatement of his/her policy within a period not later than six months from the date the first unpaid premium had become due in respect of such policy, he may deposit all the arrears of premium/premia till the date of payment alongwith interest thereon at the rates prescribed by the Director General of Posts in the Post Office specified for the purpose of payment of premia in respect of such policy and inform the CPMG to this effect alongwith a certificate of continued good health in the prescribed proforma to be signed by the insured him/herself and a certificate from his/her employers certifying that the said insured had not taken any leave on medical grounds during the period from the date the first unpaid premium had become due in respect of such policy upto the date of payment of arrears, besides a copy of the receipt (ACG-67) obtained from the said Post Office. The re-instatement of the policy shall be automatic without any further act on the part of the insured or the Department, however, subject to continued insurability of the life at the time of payment of arrears;

(i) Provided that if any payment purporting to be premium payments are made during the period of six months mentioned above and if they do not cover all the arrears together with interest thereon required to prevent the policy from becoming void such payment shall be held in suspense and shall not be considered as payment by way of premium to cover the risk of the life assured. No claim whatsoever shall lie on the Department in the event of death of the life assured during such period when premium/premia are held in suspense and the policy is not re-instated. Such premia as are held in suspense shall be refunded to the policy holder or his/her nominee, or his/her legal heir as the case may be, as and when applied for alongwith interest as prescribed by the Director General of Posts.

Note 1—Re-instatement of a policy under Rule 39(3) and Rule 40(4) shall not be allowed on more than two occasions during the entire term of a policy.

Note 2—The Director General of Posts, however, has discretionary powers in special cases to allow ex-gratia payment of the value of a policy or a part thereof, or ex-gratia refund of premia paid by the insured or part thereof, with interest or without interest, provided he is satisfied that there has been no deliberate infringement of rules with the object of using the insurance fund in a manner adversely affecting its interest and circumstances warrant payment of policy money.

2. Existing Rule 40 shall be substituted by the following;

40(1) Settlement of claims in respect of policies which have remained in force beyond thirty-six months from the date of acceptance of policy.

If in the case of a policy which has remained in force for not less than thirty-six months from the date of acceptance of the policy, and where any premium/premia have become due after such period, be not paid either on first day of the month for which the premium is due or within the period of grace allowed as per Rule 28, the policy shall cease to be active at the end of twelve months from the date the first unpaid premium had become due in respect of such policy;

i) Provided that, for the purpose of this rule an insured person is not to be considered as in arrears of premium for any month so long as he has not been able to draw his pay, pension, or subsistence allowance during suspension, or, if the insured person is on leave in India, any leave allowance though due, for the month next before it due to circumstances beyond his control. See also note-4 of rule 28 and Note below rule 36.

(ii) Provided further that the proviso (i) above shall not be applicable to the insureds who pay their premium in cash.

(2) Should the policy become a claim either due to death of the life assured or completion of the endowment period within the said period of twelve months from the date the first unpaid premium had become due, the claim for the payment of the policy shall be accepted subject to deduction of all arrears of premium/premia together with interest thereon from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due to the date of its becoming a claim at the rates prescribed by the Director General of Posts and subject further to deduction of accumulated loan and interest thereon, if any.

(3) If within the above stated period of twelve months the policy does not become a claim either due to the death of the life assured or on completion of endowment period and if no application for surrender value or paid-up policy is received within that period, the policy will be automatically kept alive only to the extent of its paid up value provided such paid up value is not less than Rupees one hundred;

(i) Provided further that if such paid up value be less than Rupees One hundred, only the surrender value shall be payable on application and further no interest shall be payable on the said surrender value;

(4) In the event of a policy-holder of a policy that has become inactive in terms of Sub-rule (1) above desiring re-instatement of his/her policy within a period not later than twelve months from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due, he may deposit all the arrears of premium/premia upto the date of payment alongwith interest thereon at the prescribed rates in the Post Office specified for the purpose of payment of premia in respect of such policy and inform the CPMG to this effect alongwith a certificate of continued good health in the prescribed proforma to be signed by the insured him/herself and a certificate from his/her employer(s) certifying that the said insured had not taken any leave on medical grounds during the period from the date the first unpaid premium had become due in respect of such policy, besides a copy of the receipt (ACG-67) obtained from the said post office. The re-instatement of the policy shall be automatic without any further act on the part of the insured or the Department subject, however, to continued insurability of the life at the time of payment of arrears;

(i) Provided that if any payment purporting to be premium payments are made during the aforesaid period of twelve months mentioned in sub-rule (4) above and if they do not cover all the arrears together with interest thereon required to prevent the policy from ceasing to be active at the end of twelve months such payment shall be held in suspense and shall not be considered as payment by way of premium to cover the risk of the life assured. No claim whatsoever shall lie on the Department in the event of death of the life assured taking place during such period when premia are held in suspense and the policy is not re-instated. Such premia as are held in suspense shall be refundable to the policy holder, his/her nominee or his/her legal heir as the case may be, as and when applied for, with interest as prescribed by the Director General of Posts at the time of such refund.

(ii) For the policies in respect of which premium is paid annually in cash in advance no refund of premium shall be allowed except in the case

of a claim arising out of death when the premium for the unexpired months shall be refunded.

Note—Reinstatement of a policy under Rule 39(3) and Rule 40(4) shall not be allowed on more than two occasions during the entire term of a policy.

3. Existing rule 41 shall be substituted by the following,

#### 41 (1) REVIVAL OF POLICIES

The Director General of Posts or the Chief Postmaster General on his behalf, may in his discretion, on receiving an application in the prescribed proforma allow a policy, which has become void in terms of rule 39(1), or has ceased to be active in terms of rule 40 (1) and has not been re-instated under the provisions of Rule 39 (3) or Rule 40(4), to be revived provided that the said policy has not attained the date of maturity and the life assured is insurable at the time of revival. Such revival shall be subject to payment, within a date to be specified by the D.G. Posts or the CPMG, of all arrears of premium with interest thereon at the rates prescribed by the D.G. (Posts) and calculated from the date the first unpaid premium in respect of such policy had become due and further subject to production of a certificate from the employer(s) that the policy holder had not taken any leave on medical grounds during the last one year, or during the entire period of service or from the date the first unpaid premium had become due in respect of such policy, whichever is last and certificate from an authorised medical agent in the prescribed proforma certifying that the life assured is insurable having regard to the insurant's health and habits and of evidence to show that there has been no change in his/her personal or family history or his/her occupation.

2. A policy shall not be considered to have been revived unless an application for that purpose has been made and until the policy has been formally revived in writing.

3. Any payments purporting to be premium/premia payments made after a policy has become void in terms of rule 39(1) or has ceased to be active in terms of Rule 40(1) but before the policy is formally revived in terms of Sub rule (1) and (2) above shall be held in suspense and shall not be considered as payments by way of premium/premia to cover the risk of life assured. No claim whatsoever shall lie on the Department in the event of death of the life assured during such period when premium/premia are held in suspense and the policy is not revived. Such premia as are held in suspense shall be refunded to the policy holder, his/her nominee or his/her legal heir as the case may be, as and when applied for, with interest as prescribed by the D.G. Posts.

4. The Director General, or the CPMG on his behalf, may at his discretion in order to revive a policy which has become void under Rule 39(1) or ceased to be active under Rule 40(1), allow the arrears of premium alongwith interest payable thereon to be paid in convenient instalments not exceeding twelve instalments, in deserving cases under a specific order to be issued in writing. In such cases the risk of the life assured shall be covered from the day the first instalment is deposited provided that subsequent instalments have been paid regularly thereafter as also the normal monthly premium besides the arrears as become due have been deposited regularly as and when due without fail. In the event of death of the insurant, who has been depositing the instalment of arrears as directed by the D.G. Posts or the CPMG besides the normal monthly premium regularly as and when due notwithstanding the fact that some arrears of premium remain unpaid at the time of death, the claim against the said policy shall be accepted subject to the deduction of such arrears of premium and interest thereon besides loan amount and interest thereon, if any, from the claim amount.

Note—The revival of a policy under rule 41 shall not be allowed on more than two occasions during the entire term of the policy which will, however, not include the relaxations given under rules 39(3) & 40(4) for re-instatement.

4. The above amendments will come into effect immediately. However, the PLI insurant who have taken their policies before the said date shall have the option to be governed by the existing rules in accordance with nota bene appearing at the beginning of the P.O.I.F. Rules corrected upto 30-9-1985 before definitions, provided they give their option in writing to such effect at the time of preferring the claim or earlier.

5. Hindi version is enclosed.

D. K. BUDKI  
Director (PLI)

New Delhi, the 17th November 1993

No. 23-2/84-LI.—The President hereby directs that the maximum limit of Insurance under the Non-Medical Scheme shall be raised from Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand) to Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh) with immediate effect.

Further the following amendments to Rule 14 of POIF Rules will come into effect immediately, namely;

In the said Rules;

Existing Rule 14 shall be substituted as follows :—

#### 14(1) Medical Scheme

In every case where the proposal for a life Assurance, Endowment Assurance or Anticipated Endowment Assurance is submitted in the prescribed form, the proposer must undergo a medical examination by the prescribed medical authority and must be declared fit for such insurance by the said authority;

(a) Provided that should a proposer, after undergoing medical examination, change his mind as to taking out a policy and decide not to proceed further with the proposal or fail to pay his first premium by the due date or should an insured person after taking out a policy, discontinue payment of premium before the policy has been in force for twelve months, he/she will be required to pay the fee prescribed in Rule 19 and 21 for the medical examination which will be recovered in cash or deducted from the next pay due to him as the case may require.

(b) The medical examination shall be carried out as per Rule 19, by the prescribed Medical authority depending upon the amount of assurance involved, and the fees on account of medical examination shall be borne by the Department in accordance with Rule 21. However, if second medical opinion is required to be obtained the fee thereof shall be paid by the proposer in case he is responsible for the delay in payment of premium beyond the specified period as per Note 1 below Rule 22.

#### (2) Non-Medical Scheme

(i) Any person, male or female, whose age next birthday does not exceed 35 years, and who is eligible for a Postal Life Insurance policy under rule 2, 2A, 2B, or 2C of the POIF Rules, with the exclusion of handicapped persons, Extra Deptil. Agents, ex-employees of P&T Department and anyone who may have applied for a life Assurance Policy either under non-Medical or Medical Scheme and had been turned down by any insurance Company operating in India, may apply in the prescribed form for a Non-Medical policy, in multiples of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand), for such sum assured which shall not exceed Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh) together with any other Non-Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold under the said Non-Medical Scheme, and further shall not exceed Rs. 2,00,000/- (Rupees two lakh) together with any Non-Medical or/and Medical policy/policies which the proposer may hold or proposes to hold.

Provided that the medical history of the propenent of reveal any adverse features, and in case such pro-falls in any category listed under Rule 2A, 2B and POIF Rules is in medical category A-1 at the time of al and had not been downgraded to a lower medical ry during the two years prior to the date of proposal.

Only Endowment Assurance policy maturing at the f 40, 45, 55, 58 and 60 shall be issued under this scheme.

i) In the event of Non-Medical policy issued under this becoming a claim before maturity, and notwithstanding total sum assured as per the said policy, the payment ust such claim shall be restricted to the following units;

a) THIRTY-FIVE PERCENT OF SUM ASSURED ONGWITH THE accrued bonus in case the death of the red person occurs before the completion of one year from date of acceptance of the proposal;

(b) Sixty percent of the sum assured alongwith the accrued bonus in case the death of the insured person occurs before the completion of two years, but not before the completion of one year, from the date of acceptance of the proposal.

(c) Ninety percent of the sum assured alongwith the accrued bonus in case the death of the insured person occurs before the completion of three years, but not before the completion of two years from the date of acceptance of the proposal.

(d) Full sum assured alongwith the accrued bonus if the death of the insured person occurs after completion of three years from the date of acceptance of the proposal.

This issues with the concurrence of Postal Finance vide their Diary No. 2956-FA/93, dated 1-11-93.

Hindi version is enclosed.

D. K. BUDKI,  
Director (PLI)

